



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ 1939 (श10)

(सं0 पटना 130) पटना, सोमवार, 12 फरवरी 2018

सं० 07 / सह० (विविध)-01 / 2016-3485  
सहकारिता विभाग

संकल्प

7 नवम्बर 2017

**विषय:-** वित्तीय वर्ष-2017-18 में 02 प्रमंडल मुख्यालय एवं 12 (बारह) जिला मुख्यालयों में सहकार भवन के निर्माण हेतु रु. 35.22 करोड़ (पैंतीस करोड़ बाइस लाख रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ का कार्यालय के अपने भवन नहीं हैं। ये कार्यालय सामान्यतः निजी परिसरों में किराये पर चल रहे हैं जिसके फलस्वरूप कार्यालय प्रबंधन में कठिनाई आती है तथा अभिलेखों का उचित रख-रखाव नहीं हो पाता है।

2. राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थान आवंटित कराने के उद्देश्य से सभी जिला मुख्यालयों में सहकार भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में सहकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है :-

- (i) प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में दो मंजिला (G+2) सहकार भवन एवं अन्य जिला मुख्यालयों में एक मंजिला (G+1) सहकार भवन का निर्माण किया जाना है। प्रमंडल स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, सहायक निबंधक का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय हेतु स्थान आवंटित है। द्वितीय तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक हेतु स्थान आवंटित है तथा तृतीय तल पर उत्कृष्टता केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित है। जिला स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय तथा प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए स्थान निर्धारित है।

- (ii) सहकार भवन के निर्माण के लिए सहकारिता विभागाधीन कार्यरत बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा सहकार भवन का मॉडल प्राक्कलन एवं नक्शा समर्पित किया गया है। योजना का स्वरूप वित्तीय वर्षवार निम्नवत है :-

योजना प्रारम्भ होने का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	प्रमंडलीय/जिला मुख्यालय की संख्या		प्रति इकाई लागत (करोड़ में)	कुल लागत (करोड़ में)
1	2		3	4
2017-18	प्रमंडल मुख्यालय	02	2.97	5.94
	जिला मुख्यालय	12	2.44	29.28
	योग			35.22

सहकार भवन का निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा किया जायेगा। सहकार भवन के निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे, द्वारा किया जायेगा।

- (iii) सहकार भवन के निर्माण के लिए दो प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा) एवं 12 जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बाँका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज एवं आरा में भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि संबंधित प्रमंडल एवं जिला मुख्यालय में कार्यरत केन्द्रीय सहकारी बैंकों/व्यापार मंडल/बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- (iv) सहकार भवन के निर्माण के लिए क्रियान्वयन विभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार होगा। तदनुसार इस मद में उपलब्ध राशि का प्रावधान माँग संख्या-3 में कराया जायेगा।
- (v) इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं समय-समय पर इस योजना हेतु निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- (vi) सहकार भवन के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 24.34 करोड़ रुपये (चौबीस करोड़ चौतीस लाख रुपये मात्र) की राशि उपलब्ध है।
- (vii) लोक वित्त समिति की दिनांक-26.07.2017 की बैठक में राज्य योजना अन्तर्गत कुल लागत रु. 35.22 करोड़ (पैंतीस करोड़ बाइस लाख रुपये मात्र) से दो प्रमंडलीय मुख्यालयों एवं 12 (बारह) जिला मुख्यालयों में कुल 14 (चौदह) सहकार भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। सहकार भवन के निर्माण की समय सीमा 02 (दो) वर्ष होगी।

उक्त के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2017-18 में 14 (चौदह) सहकार भवनों के निर्माण पर 17.61 करोड़ (सतरह करोड़ एकसठ लाख रुपये मात्र) एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 17.61 करोड़ (सतरह करोड़ एकसठ लाख रुपये मात्र) इस प्रकार कुल रु. 35.22 करोड़ (पैंतीस करोड़ बाइस लाख रुपये मात्र) के व्यय का प्रस्ताव राज्य योजना से है। साथ ही जिन प्रमंडल एवं जिला मुख्यालयों में सम्प्रति भूमि उपलब्ध नहीं है, उन प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालयों में भी भूमि उपलब्ध होने पर सहकार भवन के निर्माण हेतु चयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सहकारिता विभाग सक्षम होगा।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुरेश चौधरी,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 130-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>